भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 57
(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946(शक) को दिया जाना है।)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों संबंधी वैश्विक डेटाबेस

+57. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रत्येक सहायक कंपनी की देशवार आय का ब्यौरा जांचकर पूंजी के पलायन का विश्लेषण करने के लिए कोई वैश्विक डेटाबेस है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की पूंजी के पलायन का विश्लेषण करने के लिए कंपनियों और उनके व्यापार के संबंध में वैश्विक डेटाबेस बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को अंतर-फर्म बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापार के बारे में जानकारी है जो बीईपीएस और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के माध्यम से पूंजी के बहुत अधिक पलायन का मूल कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): ओईसीडी और जी20 बीईपीएस परियोजना का एक भाग होने के नाते, भारत कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूहों के बारे में उनकी आर्थिक गतिविधियों, आय के वैश्विक आवंटन, लाभों और करों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी को उन कर क्षेत्रों के साथ साझा करता है, जिनमें वे काम करते हैं। इस स्तर पर अभी कोई अन्य वैश्विक डेटाबेस तैयार नहीं किया जा रहा है।

(ग) : भारत सरकार इस बात से अवगत है कि अंतर-कंपनी बहुराष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप बीईपीएस के माध्यम से पूंजी का क्षरण हो सकता है। घरेलू कानून में, इस समस्या का निपटारा आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के माध्यम से किया जाता है जिसमें संबद्ध उद्यमों (जैसे एक ही बहुराष्ट्रीय समूह से संबंधित कंपनियों के बीच) लेनदेन के आर्म्स लेन्थ प्राइस (एएलपी) का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, भारत बीईपीएस परियोजना पर जी20 और ओईसीडी देशों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने की प्रवृत्ति से निपटना और कर आधारों की रक्षा करना है।

******